25 जून, 2018 को इंदौर में आयोजित यूनियन समृद्धि केन्द्र (USK) मेगा क्रेडिट कैम्प के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

- मुझे यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा हमारे किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए आयोजित यूनियन समृद्धि केन्द्र (USK) और मेगा क्रेडिट कैम्प के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।
- उल्लेखनीय है कि Techno-savy एवं आधुनिक प्रक्रियाओं को अपनाने वाली यूनियन बैंक की देश–विदेश में कुल 4214 से अधिक शाखाएं हैं जिनमें लगभग 35000 से भी अधिक बैंक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बैंक के कुल 6909 ATM देशभर में लगे हैं। कारपोरेट एवं निजी, दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रहे इस bank का financial health भी उत्कृष्ट है जिसके लिए मैं इसके प्रबंधन की सराहना करती हूं।
- यह बैंक शहरी एवं ग्रामीण आबादी, दोनों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच खुद से बढ़ाने के लिए सक्रिय नीति अपना रहा है एवं ऐसे innovative ideas ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, छोटे व्यवसायियों एवं ग्रामीण उद्यमियों के लिए उनके समक्ष लाए हैं।

- हमारे देश की दो–तिहाई जनसंख्या और 70 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में लगभग 46 प्रतिशत योगदान है। पारंपरिक रूप से भी हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि रही है और रोजगार का प्रमुख साधन भी कृषि ही है। इसलिए हमारे अन्नदाता किसान को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना हमारी सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य बन जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं समझती हूँ कि Loan की सहज और सुलभ रूप से उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान गांवों में रहने वाले लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण कृषि से होने वाली आय में कमी और मौसम और जलवायु पर कृषि की निर्भरता और इसके साथ ही Manufacturing और Service Sectors में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का उपलब्ध होना भी है। इस रूझान को बदलने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि ग्रामीणों को गांव में ही समुचित काम एवं मजदूरी मिले।

- एक सशक्त एवं प्रभावी बैंकिंग सिस्टम भारत जैसे तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंकिंग सिस्टम ही विभिन्न सरकारी स्कीमों एवं सब्सिडी को सीधे नागरिकों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण tool है। सरकार द्वारा गरीबों एवं वंचितों के उत्थान के उद्देश्य से चलाई जा रही लगभग सभी credit-related schemes का कार्यान्वयन बैंकिंग सेक्टर द्वारा किया जा रहा है।
- बैंकिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है। भारत के growth और development में बैंक और बैंक कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसको आम तौर पर वह recognition नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए

था। वे silently work करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपने कॅरियर के दौरान आप सबने निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया होगा तभी तो आज बैंकिंग क्षेत्र ने अपने वर्तमान उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त किया है।

- **प्रधानमंत्री जन–धन योजना को सफल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 30 करोड़ खाते (Jan dhan accounts) खोले जा चुके हैं जिसके माध्यम से देश के उन वंचितों एवं हाषिए पर रह रहे व्यक्तियों को देश की मुख्य आर्थिक धारा में सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण काम किया गया है। अब तक देश का एक बड़ा तबका बैंकों से जुड़ा नहीं था। इस योजना के माध्यम से लगभग 99 प्रतिषत परिवार अब तक banking system से जुड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि अब हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में कोई खाता है। Financial inclusion** की इस योजना ने देष की आम जनता को एक पहचान दी है एवं अब वे गर्व से बैंकों में जाकर अपना दैनिक कामकाज निपटाते हुए अच्छा महसूस करते हैं।

- पहले गांव का कोई किसान एवं साधारण व्यक्ति पहले बैंक जाने से संकोच और भय करता था, लोन लेने से डरता था क्योंकि समय पर लोन वापसी नहीं होने पर उनके घर की कुर्की–जब्ती भी हो सकती थी, जमीन छिन जाती थी, ऐसे पूर्वाग्रह उनके मन में थे। पर, अब काफी बदलाव आया है। ऐसी परिस्थिति में बैंक अधिकारियों ने आगे बढ़कर अपना कर्त्तव्य निभाया है। उन्होंने न केवल आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए उन्हें तैयार किया बल्कि उन्होंने उनको बचत (savings) करने की ओर प्रेरित करने का भी काम किया है।

- **बैंक अब आम जनता को भी आसानी से लोन देने लगे हैं। बैंकों और आम आदमी के बीच कड़ी का काम किसान बीमा कार्ड ने भी किया है। क्योंकि अब वे बैंकों को, और बैंक उन्हें समझने लगे है। किसानों और गरीबों को लोन देने से ये धनराशि Non-performing Assets बनने का खतरा नहीं है क्योंकि वे वापसी कर देते हैं। जबकि देखा गया है कि बड़ी–बड़ी कम्पनियों में बैंकों की बड़ी–बड़ी धनराशि Non-performing Assets बन गईं हैं।**

- बैंक वालों से आम जनता का खासकर गांव के लोगों के साथ एक विशेष प्रकार का सामाजिक और भावनात्मक रिश्ता बन गया है। वे उन्हें हर प्रकार के गाइडेंस, परामर्श एवं बचत की Nitty-Gritty बताते हैं। आम जनता को भी बैंक कर्मचारियों के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए।

- हमारे यहां बैंकिंग का एक लम्बा इतिहास रहा है। वैदिक काल से यानी 2000 बी.सी. से 1400 बी.सी. में भी भारत में money-lending operations चलन में था। बुद्धकालीन साहित्य में श्रेष्ठि अथवा बैंकर के विषय में archeological साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत के ग्रंथ मनुस्मृति में भी money-lending एवं उससे संबंधित समस्याओं के विषय में चर्चा मिलती है। General Advance के लिए उस समय 15 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज की वसूली की जाती थी।

- मौर्य काल में भी Loan deeds को ऋणलेख के रूप में जाना जाता था। बाद में वे ''आदेश'' एवं 'Letter of credit' के नाम से जाना गया। मुगल काल में इन Loan deeds को 'दस्तावेज' के नाम से जाना गया। बाद में credit instrument ''हुन्डी'' प्रचलन में आया। Colonial Period से एक नई बैंकिंग

प्रणाली अस्तित्व में आई जिसमें निरंतर कई महत्वपूर्ण सुधार हुए और अब तक होते रहे हैं।

- अब, तकनीक के उपयोग से बैंको की working style में आमूल–चूल परिवर्तन हो गया है। लेकिन बैंकिंग के मूलभूत सिद्धांत के प्रति लोगों के trust एवं confidence में कोई कमी नहीं आई है अपितु उनका बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा निरंतर बढ़ा है। यूनियन बैंक सहित भारत के सभी प्रतिष्ठित बैंक इस दौर में भी अपने shareholders and stakeholders का विश्वास कायम रखने में बहुत सफल रहे हैं। आर्थिक मंदी के समय में भी इन बैंकों ने देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूती प्रदान की है।
- भारतीय बैंक financial service providers के रूप में एक नई भूमिका में हैं। बैंकिंग कार्य की पुरानी पद्धतियों में बदलाव आया है एवं नई तकनीक ने पुरानी business processes और customer behaviour को बदलकर रख दिया है। अब वे मार्केट में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहे है। आज कल बैंकर अपनी क्षमता का optimum use कर रहे हैं। इससे ग्राहकों और बैंकों दोनों का लाभ हो रहा है।
- सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति (IT Revolution) होने के बाद बैंकिंग क्षेत्र की कार्य प्रणाली में काफी बदलाव आए हैं। इंटरनेट बैंकिंग, ए.टी.एम. सेवाओं, फोन बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे उपभोक्ताओं की आसानी के लिए दी जा रही सेवाओं से उपभोक्ताओं संबंधी कार्यों में कमी आई है। सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे DBT, Digital India Programme, Start Up India, Stand up India तथा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन में बैंकिंग सिस्टम की बहुत

महत्वपूर्ण भूमिका रही है एवं बैंक व बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्र निर्माण के इन कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- ए.टी.एम. और क्रेडिट/डेबिट कार्डों की सुविधा एवं इंटरनेट बैंकिंग ने उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों में क्रांति ला दी है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से उपभोक्ता बैंक में आए बिना ही अपने खाते को देख सकता है और उसका संचालन कर सकता है। Income Tax का भुगतान करने के लिए और विभिन्न बिलों जैसे टेलीफोन, बिजली और कर के ऑनलाइन भुगतान के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में भी ये कार्य कर रहे हैं। इससे ऐसे उपभोक्ताओं को काफी सहायता मिली है जो भुगतान करने के लिए या बैंक के अन्य कार्य के लिए लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते।
- छोटे और भुगतान बैंकों (Payment Bank) के आ जाने से वित्तीय समावेशन (financial inclusion) में तेजी आ गई है क्योंकि ये बैंक आम आदमी के द्वारा किए जाने वाले लेन–देन की लागत को कम कर रहे हैं और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों तक बैंकिंग को पहुंचा रहे हैं। इन विशेष निकायों और सार्वजनिक बैंकों के बीच साझेदारी से बैंक सूक्ष्म–ऋण (Micro Credit) और वित्तीय सेवाएं (financial services) प्रदान करने हेतु अपने नेटवर्कों का इस्तेमाल और बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
- चूंकि बड़े पैमाने पर हुए digitization से banking sector को रफ्तार मिली है और बैंकिंग कार्य संचालन में अविश्वसनीय तेजी आई है। परिणामस्वरूप cyber security के खतरे भी बढ़े हैं। इस process में बैंकिंग ग्राहकों की privacy and security दोनों प्रभावित हो रही है। अतः, strong cyber

security उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है। सम्पूर्ण बैंकिंग सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी की पुख्ता व्यवस्था करना बैंकिंग समुदाय का लक्ष्य होना चाहिए।

- **हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन में सरकार सन् 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने, कुशल श्रमशक्ति का सृजन करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना रही है और उसका कार्यान्वयन कर रही है जिसमें बैंकिंग संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होगी। चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो या अन्य कोई योजना हो, ये सभी योजनाएं बैंकों की सार्थक और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती हैं।**

- हमारे किसानों को ऋण (Loan) के माध्यम से वित्तीय समर्थन (financial help) प्रदान करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का पता इस बात से चलता है कि इस वर्ष केन्द्रीय बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए कृषि ऋण (Agriculture Loan) को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रूपये कर दिया गया है।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मार्च 2018 तक 6 लाख करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि के लोन लगभग 12 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों को ऋण प्रदान किया गया है। स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के तहत मार्च 2018 तक 54947 लाभार्थियों को ऋण (Loan) प्रदान किया गया है।

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 89766 दावों और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 16454 दावों का निपटान किया गया जिनकी धनराशि क्रमशः 1795 और 329 करोड़ रुपयों से अधिक थी। इन कार्यक्रमों से

उद्यमिता कौशल रखने वाले लोगों का वित्तपोषण करने में अत्यधिक सहायता मिली है और उन्हें बीमा कवर प्रदान करने से जोखिमों से भी उन्हें सुरक्षा प्राप्त हुई है।

- **फिर भी सच यह है कि सरकार केवल नीति निर्माण और उनका कार्यान्वयन कर सकती है परंतु घर–घर जाकर लोगों को इनके बारे में शिक्षित और जागरूक नहीं बना सकती है। लेकिन यूनियन बैंक ने ग्राहकों तक स्वयं पहुंचने एवं ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक उन्हें लोन देने का कार्य किया है, वास्तव में यह उल्लेखनीय है। यह सब बैंक के प्रयासों और प्रतिबद्धता से ही संभव है।**
- हम नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन (effective implementation) करके ही किसानों, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, उद्यमियों के जीवन में सुधार ला सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक loan उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनियन समृद्धि केन्द्र (USK) की स्थापना और मेगा क्रेडिट कैम्प लगाने का यह कदम किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों एवं छोटे व्यवसायियों के हित में हैं एवं मैं उनके इस पुनीत कार्य में पूर्ण सफलता की कामना करती हूं।
- मैं यूनियन समृद्धि केद्र (USK) और मेगा क्रेडिट कैम्प के आयोजकों को हमारे किसानों, छोटे कारोबारियों, खुदरा विक्रेताओं, स्व–रोजगार करने वाले व्यवसायियों और अन्य उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों के उद्घाटन हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इंदौर और आस–पास के क्षेत्रों के किसान और उद्यमी आपके इस प्रशंसनीय प्रयासों के माध्यम से अत्यधिक लाभान्वित होंगे।

- अब मैं लोगों की सेवा हेतु आयोजित यूनियन समृद्धि केंद्र और मेगा क्रेडिट कैम्प का सहर्ष उद्घाटन करती हूँ।

धन्यवाद।

———————